शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 7-14 अक्तूबर 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या हिमाचल राजनीतिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है?

हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उभरी आशंकाएं

शिमला/शैल। क्या हरियाणा में कांग्रेस की हार का हिमाचल सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन पर कांग्रेस हाईकमान विचार कर रही है? क्या हिमाचल में नेतृत्व के प्रति रोष मुखर होगा? यह और ऐसे ही कई सवाल हरियाणा चुनाव के बाद हिमाचल के संद्धर्भ में अचानक सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक चर्चाओं का विषय बने हुये हैं। यह शायद इसलिये हो रहा है कि जब मीडिया के एक वर्ग में हरियाणा की हार के लिये सुक्खू सरकार को भी एक कारण कहा गया तो उस पर जो प्रतिक्रिया आयी उसमें उस न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाये जाने के रूप में सामने आयी। यह एफआईआर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के अनुशंसा के बिना नहीं हो सकती। इस एफआईआर से पिछले मामले भी ताजा हो गये। जब पावर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार को लेकर एक पत्र बम्ब वायरल होकर समाचार बना था तब भी ऐसे ही एफआईआर दर्ज की गयी थी। जब मुख्यमंत्री की बीमारी को लेकर कुछ चर्चाएं उठी थी तब भी कांग्रेस के कार्यालय सचिव ने एसपी शिमला को शिकायत भेज कर ऐसी चर्चाएं उठाने वालों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने का आग्रह किया गया था। यही नहीं मीडिया के खिलाफ परोक्ष/अपरोक्ष में जो कुछ भी सत्ता कर सकती है वह सब कुछ इस सरकार में हुआ है। क्योंकि मीडिया हर सरकार के लिये स्थायी विपक्ष की भूमिका में रहता है कोई न कोई पत्रकार इस स्थायी विपक्ष के धर्म को निभाने वाला निकल ही आता है और गोदी मीडिया पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में जो सरकार मीडिया द्वारा उठाये सवालों के जवाब एफआईआर से दे उसके बारे में आम आदमी कैसे और क्या धारणा बनायेगा उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल सरकार ने अब तक के कार्यकाल में करीब पांच हजार करोड़ का राजस्व प्रदेश के आम आदमी की जेब से अर्जित किया है। जो सुविधायें पहले से मिल रही थी उन में कटौती की गयी है। यह जो 2027 में प्रदेश के आत्मनिर्भर हो जाने का दावा किया जा रहा है उसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि उस समय प्रदेश का कर्ज भार कितना होगा? क्या उस कर्ज का ब्याज प्रदेश अपने ही संसाधनों से अदा कर पायेगा? भविष्य के नाम पर वर्तमान को गिरवी रखा जा रहा है और सब चुप है। आज की सरकार पूर्व सरकार द्वारा छोड़ी गयी देनदारीयों के नाम पर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाती जा रही है। लेकिन यह नहीं बता रही है की कर्ज का निवेश कहां हो रहा है। क्योंकि सरकार अपने खर्चो पर तो कोई लगाम नहीं लगा पा रही है केवल आम आदमी की सुविधाओं पर कैंची चलाकर संसाधन बढ़ाने का काम हो रहा है।

अब जब हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है तब यह सवाल उभर कर सामने आया है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस के चुनावी वायदों पर विश्वास क्यों नहीं कर पायी? तब इसके लिये हिमाचल की व्यवहारिक स्थिति प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के हर कार्यकर्ता ने जनता के समक्ष परोसी जिसका कोई खण्डन नहीं कर सका। हरियाणा की हार से निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान कमजोर हुई है। इस कमजोरी के आधार पर हिमाचल के नेता भी अब हाईकमान को प्रदेश की व्यवहारिक स्थिति के बारे में बताने के लिये तैयार हो जायेंगे। इसके संकेत केंद्रीय सहायता को स्वीकारने के स्वरों से सामने आने लग पड़े हैं। आज तक हिमाचल में मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक हर नेता यही कहता रहा है कि केन्द्र प्रदेश की कोई सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन जे.पी. नड्डा के इस ब्यान के बाद की केन्द्र की सहायता के बिना प्रदेश सरकार एक दिन नहीं चल सकती लेकिन कांग्रेस के नेता प्रदेश में इस सहायता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जबकि केन्द्र में जाकर सहायता मांगते हैं जो मिल भी रही है। नड्डा के ब्यान के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के स्वरों में बदलाव आया है। विक्रमादित्य सिंह न केवल केन्द्र की सहायता की स्वीकारोक्ति ही कर रहें है बल्कि केन्द्र का आभार भी जता रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री केन्द्र की सहायता को स्वीकारने की बजाये यह कह रहे हैं कि केन्द्र ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस तरह मुख्यमंत्री और उनके ही सहयोगी मंत्री के स्वरों में यह विरोधाभास इसका स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में यह विरोधाभास और बड़ा आकार ले सकता है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के इस ब्यान को देखे की निष्क्रिय कार्यकर्ता की जगह नये लोगों को जगा दी जायेगी यहां पर यह सवाल उठता है कि कार्यकर्ता अभी से निष्क्रिय कैसे और क्यों हो गये हैं। सरकार के फैसलों और कार्यक्रमों को जनता तक ले जाने का काम कार्यकर्ता करता है। इस समय सरकार ने जन सुविधाओं पर कैंची चलाने का काम किया है। गांव में पानी के हर कनेक्शन पर 100 रूपये का बिल आयेगा। सस्ते राशन के चावल और आटे के दामों में 3 रूपये और 2 रूपये की वृद्धि की गयी है। पहले से मुफ्त मिल रही बिजली योजना बन्द कर दी गयी है। महिलाओं को 1500 रूपये देने पर पात्रता के इतने राइडर लगा दिये हैं कि इनकी संख्या एक तिहाई रह गयी है। सीमेंट के दामों में इस सरकार के कार्यकाल में करीब 100 रूपये की बढ़ौतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाकर बढ़ाकर वैसे ही हर चीज महंगी हो गयी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि गारंटियां देकर सत्ता में आयी सरकार का कार्यकर्ता क्या लेकर आम आदमी के पास जायेगा? कैसे वह सरकार के फैसलों को जायज ठहरा पायेगा। शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता इस व्यवहारिक स्थिति के बाद अपने को निष्क्रिय कहलाना ज्यादा पसन्द करेगा। पार्टी अध्यक्षा कार्यकर्ता की इस मनोदशा को कैसे बदल पायेगी? इसलिये देर-सवेर संगठन और सरकार में टकराव होना तय है। राज्यसभा चुनाव से पूर्व भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी एक बड़ा मुद्दा बना था और हाईकमान तक भी पहुंचा था। हाईकमान ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी जो शायद व्यवहार में कुछ कर नहीं पायी। इसलिये एक बार फिर से वही पहले वाली स्थितियां बन रही हैं। उधर ईडी की सक्रियता को लेकर नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। सहारनपुर में एक स्टोन क्रेशर की खरीद के तार नादौन से जोड़े जा रहे हैं। ईडी सूत्र इसे एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में एक साथ इतना कुछ उभरने की संभावना है जिसका राजनीतिक प्रतिफल दूरगामी होगा। फिर नवम्बर के पहले सप्ताह में सीपीएस प्रकरण का भी फैसला आने की संभावना है। क्योंकि फैसला रिजर्व होने के छः माह के भीतर इसका सुनाया जाना अपेक्षित है। इसलिये सारी स्थितियां एक साथ बनने से इनका राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू के रथ मैदान में सप्ताह भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारम्भ किया।

राज्यपाल ने भगवान श्री रघुनाथ जी की रथयात्रा में भी भाग लिया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं। राज्यपाल ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्सव के मुख्य आकर्षण स्थल पर पहुंचकर भगवान श्री रघुनाथ जी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि यह प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि कुल्लू की पवित्र भूमि में भगवान श्री रघुनाथ जी का वास है और यहां से उनका गहरा नाता है। उन्होंने कामना की कि भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रदेशवासियों पर आशीर्वाद सदैव बना रहे ताकि हम इसी प्रकार अपनी देव संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने कहा कि यह उत्सव पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है और हमें इस दौरान लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के भी प्रयास करने चाहिए।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डो, निगमों और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया और प्रदर्शनियों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता और गर्व की बात है कि मुझे आज कुल्लू की खूबसूरत घाटी में अन्तरराष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के भव्य अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहे कुल्लू के इस अनूठे उत्सव ने न केवल यहां की परम्पराओं को संजोकर रखा है बल्कि अपनी भव्यता के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान भी बनाई है।

उन्होंने कहा कि यह पवित्र त्योहार जहां एक ओर हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है वहीं रावण पर भगवान श्री राम की जीत, राक्षसों की पराजय और धर्म की पुन: स्थापना का स्मरण भी करवाता है। उन्होंने कहा कि अधर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो अंत में जीत सत्य, न्याय और सदाचार की होती है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत के अन्य भागों में जहां केवल एक दिन के लिए यह उत्सव मनाया जाता है वहीं कुल्लू में यह उत्सव सप्ताह भर चलता है और यहां देवभूमि के रीति-रिवाजों, कला और सामुदायिक भावना की शानदार झलक देखने को मिलती है। उत्सव के दौरान देवताओं की शोभा यात्रा, आकर्षक मेले और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और यहां के वातावरण को स्वच्छ और संसाधनों को संजोकर रखना हम सभी का समान दायित्व है।

राज्यपाल ने कहा कि हमें विश्वास है कि यह त्योहार समाजिक एकता को मजबूत करने, राज्य में समृद्धि लाने और हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि में नशे के लिए कोई भी स्थान नहीं है और इसे जड़ से उखाड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना चाहिए ताकि राज्य का वातावरण स्वस्थ बना रहे।

इस अवसर पर जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों से 300 से अधिक देवता भाग ले रहे हैं।

इससे पूर्व, भूंतर हवाई अडडे में आगमन पर राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक, उपायुक्त तोरूल एस रवीश, पुलिस अधीक्षक डॉ. कार्तिकेयन गोकुल चन्द्रन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने प्रीणी स्थित अटल आवास का किया दौरा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला कुल्लू के चार दिवसीय प्रवास के दौरान मनाली पहुंचने पर प्रीणी स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास का दौरा किया। उन्होंने परिसर में कुछ समय व्यतीत किया और श्री अटल जी के साथ बिताए पलों और स्मृतियों को याद किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रहीं। अटल जी को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें हिमाचल और यहां के लोगों से विशेष बहुत लगाव था। वह इसे अपना दूसरा घर मानते थे। यहां के शांतिपूर्ण माहौल में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं।

राज्यपाल ने रोरिक आर्ट गैलरी और नग्गर कैसल का दौरा भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि महान कलाकार निकोलस रोरिक ने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से हिमाचल की खूबसूरती को चित्रों में उकेरा है। यह गैलरी भारत और रूस के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करती है।

इससे पहले, राज्यपाल ने काईस मॉनेस्ट्री का भी दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की दशहरा उत्सव पर प्रदेशवासियों को बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के लोगों को दशहरा उत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारे नैतिक मूल्यों और परम्पराओं को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा।

हिमाचल को पांच परियोजनाएं समर्पित करने के लिए राज्यपाल ने रक्षा मंत्री का आभार जताया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा प्रदेश में निर्मित पांच महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देशभर में बुनियादी ढांचा विकास के लिए निर्मित 75 परियोजनाओं में प्रदेश के लिए पांच महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है।

राज्यपाल राजभवन से आभासी वर्चुअल माध्यम से इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से भारत-चीन सीमा पर सम्पर्क और सामरिक महत्व की सड़कों, पुल व अन्य तैयारियों को बल मिलेगा। यह परियोजनाएं न केवल सेना और उपकरणों की आवाजाही को सुदृढ़ करने बल्कि स्थानीय लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

शुक्ल ने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों और खराब मौसम की स्थिति में भी समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ कर्मियों के साहस और दृढ़-संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में एनएच-3 मनाली-सरचू सड़क, एनएच-5 पोवारी-पूह-खाब-नामगिया- चुप्पन-शिपकिला सड़क और एनएच-505 खाब-समदो-काजा-ग्रांफू सड़क पर मुन्नी 40 मीटर, भागा 30 मीटर, डोगरी 65 मीटर, हबसर 50 मीटर और शलखर-11 45 मीटर सहित पांच पुलों का निर्माण शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन हाइब्रिड मोड पर किया गया है जो राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों के लिए जीवन-रेखा का कार्य करेंगी।

राज्यपाल ने कहा कि बीआरओ ने राज्य में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया है और इनमें से कई परियोजनाओं का निर्माण एक ही कार्य सत्र में अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है।

जुन्गा दशहरा में स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बनी लोगों की पहली पसंद

शिमला/शैल। राजधानी शिमला के समीप जुन्गा में आयोजित तीन दिवसीय दशहरा पर्व के अवसर पर जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद लागों की पहली पसंद बनी। वन परिक्षेत्र कोटी, मशोबरा और तारादेवी के स्वयं सहायता समूहों ने यहां प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए, जिसमें पहाड़ी शहद, आचार और पाइन नीड्ल प्रोडक्ट्स उपलब्ध थे। दशहरा पर्व का लुत्फ उठाने पहुंचे ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूहों के प्राकृतिक उत्पाद खरीदने में खूब रुचि दिखाई। मेले के दूसरे दिन 25 हजार रुपये से अधिक की ब्रिकी हुई। वन परिक्षेत्र कोटी के अंतर्गत उमंग, सरस्वती और सशद्र महिला स्वयं सहायता समूह, वन परिक्षेत्र मशोबरा के अंतर्गत उमंग और कोरगन देवता स्वयं सहायता समूह और वन परिक्षेत्र तारादेवी के अंतर्गत राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह के उत्पाद मेले में आकर्षण को मुख्य केंद्र बना। मेले के दौरान रस्सा-कस्सी खेल का आयोजन भी किया गया। जिसमें उमंग स्वयं सहायता समूह और सरस्वती स्वयं सहायता समूह की मिक्स टीम ने बाजी मारी और 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिला।

जूनियर ड्राफ्ट्समैन भर्ती की तिथि निर्धारित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जूनियर ड्राफ्ट्समैन (सिविल) की अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। अभ्यर्थी पात्रता के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के साथ 15 अक्तूबर 2024 को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय निर्माण भवन, एचपीपीडब्ल्यूडी, निगम बिहार, शिमला-2 में पहुंचे। अभ्यार्थियों को डाक के माध्यम से कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। पात्रता व अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग के दूरभाष नम्बर 0177-2621401, 2621403 और 2625492 पर संपर्क कर सकते हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

पालमपुर में मुख्य एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा स्थापित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 'समर्थ-2024' की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में जागरूकता महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा

करती है, जिससे जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित कर हमें इन चुनौतियों के साथ जीना सीखना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि व्यय कर लोगों को आपदा से निपटने की तैयारियों के बारे में जागरूक कर रही है और आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण को सदैव तैयार रहना चाहिए। इस दिशा में फ्रांस की एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटीगेशन फंड से 500 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक मुख्य एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी की। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए बुनियादी अधोसंरचना को भी सुदृढ़ कर रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का शुभारंभ किया और हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की। सरकार की इस पहल को सीबीआरआई रुड़की, एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ और एनआईटी हमीरपुर की तकनीकी विशेषज्ञता का सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बाल रक्षा भारत और जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सहयोग से जिला सोलन की ग्राम पंचायत बवासनी में रेजिलिएंट मॉडल विलेज विकसित करने के लिए रीबिल्डिंग लाइव नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए ने प्रदेश में इंजीनियरों, वास्तुकारों, बिल्डरों और राज मिस्त्रियों के कौशल उन्नयन के लिए सीबीआरआई रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिला कांगड़ा के रैत में एएफडी कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन इकाई टीडीयू स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय भवन अनुसंधान रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशन कवच-1 व कवच-2 का विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित किया और इस म नसून के दौरान समेज, बागीपुल, राजबन में बादल फटने की घटनाओं के दौरान किए गए असाधारण राहत कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु युवा स्वयंसेवियों की टास्क फोर्स के लिए जिला कांगड़ा और चम्बा को 'सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिला' पुरस्कार से सम्मानित किया।

कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण

घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है।

उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधाान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देने की घोषणा की।

इस अवसर पर उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है।

ऑनलाइन उपलब्ध होंगे ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले विवाह, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले विवाह, जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विभिन्न जन सेवाएं उनके घर-द्वार के समीप सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए

प्रतिबद्ध है। वह ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास से ही प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 275 लाख श्रम दिवस अर्जित करने के लक्ष्य के मुकाबले 344.31 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 300 लाख श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 214.51 लाख श्रम दिवस अर्जित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 17,582 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस म डल बनाए जाएंगे। अभी तक 9203 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस म डल घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 2347 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस वेरीफाइड हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास खंडों में 32 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है और 26 को कार्यशील कर दिया गया है। ऐसी इकाइयां सभी विकास खंडों में निर्मित की जा जाएंगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अभी तक 43,161 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिन्हें समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एसआरएलएम के तहत नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय के लिए 93 हिम ईरा दुकानें उपलब्ध करवायी गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इनमें 1.4 करोड़ रुपये के उत्पाद विक्रय किए गए हैं। एसआरएलएम द्वारा 80 सप्ताहिक बाजारों वीक मार्किटस भी लगाए जाते हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2023-24 में 1.2 करोड़ रुपये के उत्पाद विक्रय किए गए। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें बेहतरीन विपणन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को हिम ईरा प्रीमियम ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन उत्पादों को प्रतिष्ठित संस्थानों में विक्रय के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस अवसर पर हिम ईरा के ब्रांड के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यन्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा समन्वय से प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव ग्रामीण विकास राजेश शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनआरएलएम शिवम प्रताप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बेंगलुरु में कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार के साथ शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाइड्रो

पावर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समग्र उपयोग सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है और राज्य में हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

डी.के शिव कुमार ने तकनीकी थे। शिक्षा मंत्री को इन क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया।

इसके उपरांत तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कर्नाटक के इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सिटिजन सर्विसिज निदेशालय का दौरा कर सिटिजन सर्विसिज सेवा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। ईडीसीएस के माध्यम से लोगों को तकनीकी रूप से एकीकृत तरीके से 850 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह के नवाचार अपनाने के प्रयास किए जाएंगे।

राजेश धर्माणी ने कर्नाटक में तकनीक कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे विविध आयामों को जानने के लिए टीम लीज डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के सीईओ नीति शर्मा से भेंट की। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने उद्योग आधारित कुशल कार्यबल और पाठयक्रमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रदेश व कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। ..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

राज्यों में विश्वसनीय नेतृत्व का अभाव है -कांग्रेस की समस्या

हरियाणा में कांग्रेस की हार बहुत लोगों के लिये अप्रत्याशित है क्योंकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और आकलनों में किसी ने भी इस हार के प्रति इंगित नहीं किया था। जब प्रधानमंत्री ने हिमाचल की सुक्खू सरकार की असफलताओं को हरियाणा और जम्मू – कश्मीर में चुनावी मुद्दा बनाकर उछाला तब शैल को यह आशंका हो गयी थी कि चुनाव परिणाम उम्मीदों के विपरीत होंगे। शैल के पाठक जानते हैं कि हमने 16 सितम्बर के अंक में पूरे विस्तार से लिखा था कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है। केवल हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में उसकी सरकारें हैं। इसलिये कांग्रेस जब भी किसी राज्य के चुनाव में अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उस राज्य के लिये अपने वायदे रखेगी तो उन वायदों की पड़ताल उसकी राज्य सरकारों की परफारमैन्स से की जायेगी यह स्वभाविक है। हिमाचल हरियाणा का पड़ोसी राज्य है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन से हरियाणा और वर्तमान हिमाचल निकला है। भाखड़ा विस्थापितों का पुनर्वास भी हरियाणा में हुआ है। लगभग एक दर्जन विधानसभा सीटों पर इन विस्थापितों का निर्णायक प्रभाव है। यह विस्थापित हिमाचल से हर समय जुड़े हुये हैं। इसलिये हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स के लिये इन्हें किसी अन्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स अपने ही कारणों से अपनी ही दी हुई गारंटीयों के आईने में पूरी तरह असफल रही है। इस असफलता के कारण हरियाणा का मतदाता कांग्रेस के वायदों पर विश्वास नहीं कर पाया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री स्वयं विवादों में घिरे हुये हैं। इसलिये कांग्रेस पर विश्वसनीयता बना पाने में आम आदमी निर्णायक नहीं हो पा रहा है।

हरियाणा में कांग्रेस की हार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर मुद्दा है। हरियाणा में भाजपा ने भी मुफ्ती की घोषणाओं के सहारे सत्ता पायी है। मुफ्ती के वायदों पर आरटीआई से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक का जो रुख रहा है उसका हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं दिखा है। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने आरबीआई और सर्वोच्च न्यायालय को खुलकर अंगूठा दिखाया है। मुफ्ती के वायदों को भाजपा कैसे पूरा करती है और उसका हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आने वाला समय ही बतायेगा। इस समय हरियाणा बेरोजगारी में शायद देश में पहले स्थान पर है। किसान आन्दोलन का केंद्र हरियाणा रहा है। शायद इसी के कारण यह माना जा रहा था कि अब भाजपा प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जायेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि जब नरेन्द्र मोदी का रथ लोक सभा चुनाव में चार सौ पार के नारे के बाद दो सौ चालीस पर रुक गया और नीतीश तथा चन्द्रबाबू नायडू के सहारे सत्ता तक पहुंचे तब यह स्पष्ट हो गया था कि अब जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे उन्हें येनकेन प्रकरेण भाजपा जीतने का प्रयास करेगी। हरियाणा में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का बदला जाना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। इसी रणनीति के तहत वक्फ संशोधन विधेयक लाना और उस पर राष्ट्रीय बहस चलवाना तथा इसी बीच एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट आना कुछ ऐसे संकेत बन जाते हैं जिन से भविष्य का बहुत कुछ समझा जा सकता है। कांग्रेस के रणनीतिकार और विश्लेषक इसका आकलन नहीं कर पाये।

इस समय जो राजनीतिक वातावरण निर्मित हो रहा है उसमें अधिकांश दलों में और विशेषकर कांग्रेस के अन्दर ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो अनचाहे और बिना समझे ही हिन्दू एजैण्डे के ध्वजवाहक बने हुये हैं। जबकि यह एजैण्डा एक राजनीतिक एजैण्डा बनकर रह गया है। इस स्थिति को समझने की आवश्यकता है। सारा एजैण्डा आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने की रणनीति है। इसलिये आज कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये राज्य सरकारों की परफॉरमैन्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस को लोग राहुल गांधी के ब्यानों से ज्यादा पार्टी की राज्य सरकारों की परफारमैन्स से आंकेंगे। क्योंकि जब से आरटीआई और सर्वोच्च न्यायालय ने मुफ्ती की घोषणाओं पर कड़ा रुख दिखाया है तब से आम आदमी सरकारों की कर्ज संस्कृति पर भी नजर रख रहा है । आज हिमाचल में सरकार जिस तरह से प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में डालकर घी पीने का काम कर रही है उसे आम आदमी पसन्द नहीं कर रहा है। इसलिये हरियाणा की हार को ईवीएम गड़बड़ी करार देने से पहले कांग्रेस को अपनी राज्य सरकारों की जन स्वीकार्यता का आकलन करना होगा। क्योंकि हरियाणा की हार की कीमत महाराष्ट्र और झारखंड में चुकानी पड़ सकती है। इंडिया के सहयोगी दल भी कांग्रेस के प्रति अलग राय बनने पर विवश हो जाएंगे। जब तक राज्यों में विश्वसनीय नेतृत्व नहीं आ पाता है तब तक कांग्रेस के लिये भविष्य आसान नहीं होगा।

स्मार्ट क्लास रूम में एलइडी स्क्रीन पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तौर – तरीका अब बदल रहा है। यह संभव हुआ है प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए सार्थक कदमों से। मंडी जिला के पधर उपमंडल के खंड द्रंग – 2 के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्कूलों में छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लास रूम में एलइडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर द्वारा भी पठन – पाठन की सुविधा राजकीय प्राइमरी स्कूलों में मिल रही है।

बदलते परिवेश के साथ आधुनिक तकनीकी व प्रौद्योगिकी से कदम – ताल समय की आवश्यकता है। हाथों में स्लेट व लकड़ी की पट्टी तथा कलम – दवात से आगे बढ़कर अब टैक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव साफ नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण एवं अत्याधुनिक सुविधाएं प्रारम्भिक स्तर से ही प्रदान की जा रही हैं। सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों को स्मार्ट क्लास रूम व एलईडी स्क्रीन पर शिक्षा प्रदान करने की पहल की गई है।

प्रदेश सरकार के प्रभावी कदमों का सुपरिणाम अब धरातल पर भी नजर आने लगा है। मंडी जिला भी इस पहल का गवाह बना है। जिला मुख्यालय के साथ सटे द्रंग क्षेत्र में प्री – प्राइमरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चे आधुनिक तौर – तरीकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकीय केंद्रीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला नारला इन्हीं में से एक है। इस पाठशाला में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहां पर स्मार्ट कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। इस सत्र में पाठशाला में कुल 112 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक हैं।

खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमारी ने बताया कि सत्र 2024 – 25 के लिए द्रंग खंड में प्री – प्राइमरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक 2096 विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। द्रंग – 2 प्राथमिक शिक्षा खंड में कुल 95 विद्यालय हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। इनमें से 20 राजकीय केंद्रीय उत्कृष्ट प्राथमिक पाठशालाओं में स्कूलों में एलइडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

पधर की कमलेश और संतोष ठाकुर कहती हैं कि उनकी बेटी राजकीय केंद्रीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला नारला में पढ़ती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की पहल की गई है। ऐसे में अब उनकी बेटी भी कम पैसे में सरकारी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रही है और स्मार्ट कक्षा की सुविधा भी उन्हें मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बहुत – बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं।

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर शुरू किया फास्ट फूड उद्यम हर माह कर रही 20 हजार रुपए की कमाई

शिमला। थोड़ा सा उत्साह, अपनों का साथ और सरकार का मदद वाला हाथ। इन तीनों ने उर्मिला को सामान्य गृहिणी से एक उद्यमी के रूप में स्थापित होने तथा आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है।

ग्राम पंचायत भडयाल की उर्मिला की जिंदगी कुछ साल पहले तक एक गृहिणी के रूप में ही बीत रही थी। बच्चों का लालन – पालन, घर – गृहस्थी संभालने में उनके दिन गुज़र रहे थे। इसी बीच वह बाला कामेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और इसके बाद ही उनके हौसले भी परवान चढ़ने लगे। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त हुई। महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार की दिशा दिखाने में यह समूह उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं, इसका अहसास अब उर्मिला को बखूबी हो चुका था।

उर्मिला ने बताया कि उनके पति गोपाल सिंह निजी क्षेत्र में मोटर मैकेनिक का कार्य करते हैं। पति का हाथ बंटाने के लिए उन्होंने पहले कपड़ों का व्यापार शुरू किया, मगर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उसमें ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम पहले 50 हजार रुपए तथा बाद में एक लाख रुपए का ऋण लिया और फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) के तहत भी 40 हजार रुपए की ऋण राशि प्राप्त हुई है। भडयाल बाजार में जालपा फास्ट फूड के नाम से शुरू किया गया उनका व्यवसाय अब अच्छे से चल निकला है। बकौल उर्मिला इससे उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपए से अधिक की शुद्ध आय हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस उद्यम को शुरू करने में उनके पति का निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। अब वे इसे विस्तार देने पर भी विचार कर रहे हैं। परिवार की आय बढ़ने से अब अपने दो बच्चों की शिक्षा व अन्य जरूरतें पूरी करने में वह सक्षम हुई हैं। उर्मिला ने बताया कि सरकार की इस तरह की योजनाओं एवं प्रोत्साहन से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वरोजगार व स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से ऋण राशि एक प्रतिशत की न्यूनतम दर पर प्राप्त होने से उनकी आर्थिक चिंता कुछ कम हुई और वे यह व्यवसाय शुरू कर पाई हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट मोबलाइजेशन के तहत वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 – 24 में जिला में इसके तहत लगभग 29 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि वितरित कर 1257 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2024 – 25 की प्रथम तिमाही में दो करोड़ 51 लाख रुपए की राशि वितरित कर 95 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न उद्यमों के लिए ऋण राशि वितरित की गई है।

बेहतर सम्पर्क सुविधा सृजन से लोगों के जीवन में सुगमता ला रही प्रदेश सरकार

2024-25 में बुनयादी ढांचे को विकसित करने के लिए में 2,240.27 करोड़ रुपये का प्रावधान

शिमला। सड़कें विकास की भाग्य रेखाएं होती हैं। बिना सड़क निर्माण के विकास कार्य संभव नहीं हो सकते। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का योगदान बेहद अहम है। हालांकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है फिर भी प्रदेश सरकार विकास के ध्येय के साथ निरंतर प्रयासरत है।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग इस मिशन में सबसे आगे है तथा दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़क नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए निरन्तर कार्य कर रहा है।

वर्तमान में प्रदेश का सड़क नेटवर्क 41,202 किमी है जिसमें 34,917 किमी पक्की सड़के हैं जिनके माध्यम से सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित हो रही है। लोक निर्माण विभाग ने 2,519 पुलों और 36,763 किमी क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया है। पहाड़ी क्षेत्र में भू-स्खलन, मानसून और सर्दी के मौसम में सड़कों पर आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए पुल और क्रॉस ड्रेनेज होना बहुत आवश्यक है।

राज्य के 17, 882 गांवों में से 15, 778 को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है जिसके फलस्वरूप ग्रीमाणों को स्कूल, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। 12,500 करोड़ रुपये के निवेश से फोरलेन राजमार्ग और 68 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजनाएं यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ पर्यटन और कारोबार तक पहुंच में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण साबित होंगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस वित्त वर्ष 2,240.27 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें से 526. 42 करोड़ रुपये की धनराशि का बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग किया जा चुका है। इस धनराशि से वर्ष के पहले छह माह में 18 पुल, 33 नए भवन, 190 किमी परिवहन योग्य सड़कें और 309 किमी क्रॉस-ड्रेनेज बुनियादी ढांचे सहित अनेक कार्यो का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

इसके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 674 किमी सड़कों की टारिंग और 1,060 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है।

लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य लगभग पूर्ण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-प् का 99 प्रतिशत और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-पप् का 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप अब हजारों गांव बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़ गए हैं। लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है और वह समृद्धि और खुशहाली की तरफ अग्रसर हैं।

प्रदेश सरकार के प्रयासों से 2024-25 में केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि सीआरआईएफ के तहत 293.36 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि का उपयोग प्रदेश की पांच प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। शिमला में 52 किमी लंबी टिक्कर- जरोल-गाहन -ननखड़ी-खमाड़ी सड़क का उन्नयन, कांगड़ा में गज खड्ड पर एक पुल और हमीरपुर और मंडी जिलों में उन्नयन कार्य किया जाना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। यह राज्य के सभी क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने परिचालन को सुव्यवस्थित करने और परियोजना प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए वामिस (WAMIS) सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सरकार ने निविदा प्रक्रिया की अवधि भी 51 दिनों से 30 दिन कर दी है। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों को उच्च-मूल्य वाली निविदाओं को स्वीकृति देने के लिए ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी आई है।

सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यो में गुणवत्ता नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि गुणवत्ता के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कड़ी निगरानी की जा रही है और गुणवत्ताविहीन कार्य करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सड़क बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए कार्य राज्य के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहे हैं।

प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़क कनेक्टिविटी द्वारा राज्य की जनता को समान आर्थिक समृद्धि के अधिक से अधिक अवसर तथा बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य सरकार के अथक प्रयास न केवल कनेक्टिविटी में बदलाव ला रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश को प्रगति और विकास के एक म डल के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य में सम्पर्क मार्गो की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होने से विकास को निरन्तर गति मिल रही है और प्रदेश म डल राज्य के रूप में स्थापित होने की ओर निरंतर अग्रसर है।

एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना

अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस

राजन कुमार शर्मा,
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

हर साल बढ़ती आपदाएं, जिनमें से कई जलवायु परिवर्तन से प्रेरित और तीव्र होती हैं, बच्चों और युवाओं की भलाई के लिए खतरा हैं। यूनिसेफ के अनुसार, जलवायु संबंधी आपदाओं सहित जलवायु प्रभावों के कारण दुनिया भर में लगभग एक अरब बच्चे अत्यधिक जोखिम में हैं। 2022 में, चाड, गाम्बिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बाढ़ से प्रभावित बच्चों की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक थी। मृत्यु और चोट के जोखिम से परे, आपदा के बाद बच्चों को स्कूली शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा मुद्दों में व्यवधान जैसे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को आपदाओं से बचाने के लिए, देशों को राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को डिजाइन करते समय उनकी कमजोरियों और जरूरतों पर विचार करना चाहिए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाया जाए और उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान करने के लिए स्थान और तौर-तरीके प्रदान किए जाएं, जैसा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में कहा गया है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा की राजनीतिक घोषणा के कार्यवाही के आहवान के साथ भी संरेखित है, जिसमें युवाओं की पूर्ण, समान, सार्थक और समावेशी भागीदारी और आपदा रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देने का आहवान किया गया है। बच्चों को सशक्त बनाना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम से, उन्हें खुद की रक्षा करने और अपने परिवारों और समुदायों में परिवर्तन के एजेंट बनने में सक्षम बना सकता है, जो उन्होंने सीखा है उसे साझा करके। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विस्तार करने के वैश्विक प्रयास के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। वैश्विक आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) 2024 का विषय आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका पर होगा। यह विषय सितंबर 2024 के लिए नियोजित आगामी शिखर सम्मेलन के साथ संरेखित है, जहाँ युवा और भावी पीढ़ियाँ इसकी पाँच प्राथमिकताओं में से एक होगी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 देशों से स्कूली बच्चों के आपदा जोखिमों को कम करने के लिए शिक्षा क्षेत्र का उपयोग करने का आहवान करता है, विशेष रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में निवेश सुरक्षित स्कूलों और शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा करें: बच्चों को अपने स्कूलों में सुरक्षित रहने का अधिकार है और इसकी शुरुआत यह सुनिश्चित करने से होती है कि स्कूल आपदा-प्रतिरोधी हों और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों का हिस्सा हों। बच्चों और युवाओं को उनके सामने आने वाले जोखिमों को समझने और उन पर कार्रवाई करने के लिए आयु-उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रहने के लिए सशक्त बनाएँ। इसमें प्रारंभिक चेतावनियों के जवाब में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनकी तैयारी का निर्माण करना शामिल है। सशक्त बच्चे अधिक लचीले समुदायों के लिए परिवर्तन के एजेंट बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिए वैश्विक गठबंधन द्वारा विकसित व्यापक स्कूल सुरक्षा रूपरेखा 2022-2023 का समर्थन और कार्यान्वयन करें, जिसकी अध्यक्षता यूनेस्को और यूनिसेफ करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एच.पी.एस.डी.एम.ए. 2011 से हर साल आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम अपने 14 वें संस्करण में है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने समस्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य में 1 अक्तूबर से 30 अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न प्रकार की आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को संचालित कर रहा है। जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षित भवन निर्माण संबंधी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी व आभासी बैठकें, सुरक्षित भवन निर्माण म डल, आपदा जागरूकता रैलियां, सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री द्वारा प्रचार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व निजी योगदान, सर्वोत्तम गैर सरकारी संगठन, सर्वोत्तम स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं, इसके अतिरिक्त समस्त जिलों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से विभिन्न नृत्य एवं कला मंचों के माध्यम से आपदाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एकमात्र लक्ष्य राज्य में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से आमजन को सुरक्षित एवं जागरूक करना है ताकि इस पर्वतीय क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं से समुदाय एवं अति संवेदनशील श्रेणी के लोगों को भविष्य में सुरक्षित रख पाने में मदद मिल सके। युवा लोग सिर्फ़ निष्क्रिय पीड़ित नहीं हैं। उन्हें नेता के रूप में सक्रिय भूमिका निभानी है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समाधानों में सहयोग और सह-निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री ने 73वें वन्य जीव सप्ताह में मोनाल पक्षी को गोद लेने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 73वें वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मोनाल पक्षी को गोद लेने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों से प्रदेश के पार्कों और चिड़ियाघरों में रखी विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों को गोद लेने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जानवर को गोद लेने से न

केवल उनकी देखभाल करने में मदद मिलती है बल्कि प्राकृति के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रति मनुष्य की समझ और प्रतिबद्धता और अधिक गहरी हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने तीतर प्रजातियों के संरक्षण पर व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की भी घोषणा की। यह समिति इस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत प्रजाति को देख सकें और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघरों के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को इस प्रणाली का लाभ मिलेगा और राजस्व के स्रोत भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे अर्जित होने वाले आय को वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन और अधोसंरचना विकास पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने स्पीति घाटी के 'सरचू' के संरक्षण रिजर्व के रूप में शामिल करने की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य यहां के पारिस्थितिकी और वन्य जीव गलियारों की रक्षा करना है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक सुन्दरता, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और अनमोल वन्य जीव न केवल प्रदेश की विरासत हैं बल्कि यहां के लोगों की जीवन रेखाएं भी हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है ताकि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हांलाकि प्रदेश सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वन्य जीव संरक्षण एक सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि जब तक हम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक वन्य जीवों की सुरक्षा अधूरी है।

उन्होंने वनों को प्रदूषण और अवैध शिकार से बचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वन्य जीव गतिविधि से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए मुआवजा योजनाओं के अलावा विभिन्न पहल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूल और संरक्षण कार्यक्रम भी लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों और इनके प्रति लोगों के अटूट स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल बर्फानी तेन्दुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन थार और काले व भूरे भालु जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है और प्रदेश सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वनों में आग लगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और रोकथाम के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत देहरा में 680 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस चिड़ियाघर का पहला चरण जून-2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्गेश अरणय ज्यूलोजिकल पार्क और स्पिति वाइल्ड लाइफ डिविजन के लिए दो नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने फिल्ड कम्पेंडम ऑन रेस्क्यू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन डिस्ट्रैस एंड देयर रेसक्यू, आरचिडस ऑफ शिमला वाटर केचमैंट, स्पितिज नेचुरल टेपेस्ट्री और द मैनेजमैंट प्लेन ऑफ पॉटर्स हिल कंजर्वेशन रिजर्वस जैसे प्रकाशनों का भी अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने जिला शिमला के तहसील ठियोग के लायक राम और शवानु राम को वन्यजीव संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य तथा वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

विधायक हरीश जनारथा, महाधिवक्ता अनूप रतन अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल एचओएफएफ पवनेश शर्मा और पीसीसीएफ वन्य जीव अमिताभ गौतम, उपायुक्त अनुपम कश्यप और वन विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने जाखू में किया रावण दहन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दशहरे के शुभ अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में

पूजा-अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन भी किया।

विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, स्थानीय पार्षद अतुल गौतम, नगर निगम के अन्य पार्षदगण, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सरकार के प्रयासों से युवाओं को विदेश में प्राप्त हुए रोजगार के अवसर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार की युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पांच युवाओं का पहला बैच अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इन युवाओं

को 31 अगस्त, 2024 को शिमला में नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे।

इन युवाओं में ऊना जिला के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह और अभिनव तथा जिला हमीरपुर के दिनेश शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूएई स्थित दुबई में ईएफएस फैसिलिटीज़ सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया है। दिसम्बर, 2023 में मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के उपरांत इएफएस ने विदेश भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल से 15-20 प्रतिशत भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत आतिथ्य, तकनीकी सेवाओं, हाउस कीपिंग, खाद्य व पेय पदार्थ और कार्यालय सहायक जैसे क्षेत्रों में प्रदेश से प्रतिवर्ष लगभग 1000 उम्मीदवारों को दुबई में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में कार्य कर रहे युवाओं का कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रदेश सरकार की विदेश में राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सिर्फ 20 माह के अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31000 पद सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है ताकि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में और अवसर प्राप्त हों। इस पहल से राज्य के युवा ऐजेंटों के शोषण से बचेंगे और विदेश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना भी आरम्भ की है। इस योजना से राज्य के युवा स्वयं के उद्यम और स्थायी आजीविका अर्जन के लिए प्रेरित होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे।

खेल खिलाड़ी टैक्स योजना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे नेता प्रतिपक्ष:यादविन्द्र गोमा

शिमला/शैल। युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर प्रदेश में खेल खिलाड़ी टैक्स योजना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने खिलाड़ियों से टैक्स वसूले जाने संबंधी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा एथलेटिक ट्रैक धर्मशाला और बिलासपुर में खिलाड़ियों और खेल संघों से कोई भी धनराशि नहीं ली गई है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि विभाग द्वारा खिलाड़ियों से ट्रायल और खेल उपकरणों के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है। जिला खेल परिषद् द्वारा हर खेल परिसर के लिए निर्धारित शुल्क सारे तथ्यों के आकलन करने के पश्चात ही तय किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि इण्डोर स्टेडियम बिलासपुर की दर वर्ष 2014 और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिलासपुर की दर वर्ष 2021 में निर्धारित की गई है। इण्डोर स्टेडियम और सिंथेटिक एथलेटिक बिलासपुर में खेल संघ और सरकारी संस्थानों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 5000 रुपये और निजी संस्थानों के लिए 10,000 रुपये तय की गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी नया शुल्क नहीं लगाया गया है।

इस राशि का उपयोग सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के रख रखाव के लिए किया जाता है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभावान और उदीयमान खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार द्वारा उन्हें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को खेल भूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य की खेल प्रतिभाओं को उपयुद्र मंच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की डाइट मनी में वृद्धि करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, जिला स्तर के लिए 300 रुपये और खंड स्तर के लिए 240 रुपये किया गया है। राज्य से बाहर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 500 रुपये की गई है। प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली यात्र सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही वर्तमान में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विंटर ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच-पांच करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को तीन-तीन करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को दो-दो करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। इसके साथ ही एशियाई और पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को चार करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1.50 करोड़ प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने की असफल कोशिशों से प्रदेश की जनता भली-भांति वाकिफ है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बधाई देते हए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में एचआरटीसी की अतुलनीय भूमिका रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान परिवहन निगम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रदेश की घुमावदार सड़कों से आरम्भ हुई एचआरटीसी की यात्रा आज आरामदेह सफर और विश्वास का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की 50 वर्षो की सफल यात्रा में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अदम्य कौशल का

महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने इस माह एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों की पेंशन 28 अक्तूबर को प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों के 55 माह के ओवर टाइम की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपये प्रदान करेगी तथा 31 मार्च, 2025 तक ओवर टाईम का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के 9 करोड़ रुपये के लम्बित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आगामी दो माह में कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी तथा 31 मार्च, 2026 तक आत्मनिर्भर निगम बनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक एचआरटीसी अधिकारियों के सभी वाहन इलैक्ट्रिक वाहन से बदल दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने निगम से जुड़ी मधुर स्मृतियों को सांझा करते हुए कहा कि एचआरटीसी ने 50 वर्षो में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने एचआरटीसी से आगामी 50 वर्षो की योजना पर भी कार्य करने को कहा। उन्होंने कर्मचारियों से एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया तथा कहा कि वर्ष 2026 तक प्रदेश सरकार निगम को विद्युत ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है। निगम की बसों में ग्रीन हाईड्रोजर्न इंधन के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इन सकारात्मक उपायों से एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को ठीक कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में सार्थक प्रयास कर रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ एचआरटीसी को भी आर्थिक तंगी से उबारने के प्रयास किये जा रहे हैं। निगम की अधोसंरचना विकास व उन्नययन के साथ-साथ इसके कर्मचारियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। एचआरटीसी के लगभग 7,300 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है और 1,546 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया है। परिवहन निगम में 608 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और 550 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। एचआरटीसी के 421 कर्मचारियों को पदोन्नती का लाभ दिया गया है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान निगम के बेड़े में 210 नई साधारण बसें, 11 वोल्वों बसें और 35 इलैक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। निगम को सशक्त करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। वर्तमान में 297 टाइप-एक इलैक्ट्रिक बसें, 30 वातानुकूलित टाइप-3 इलैक्ट्रिक बसें, 50 मिनी व मिडि बसें और 24 वोल्वों बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने एचआरटीसी को इलैक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। इसके अलावा दो हजार टाइप-दो इलैक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने में एचआरटीसी की भूमिका अभिन्न है। इसके लिए एचआरटीसी में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। सरकार इसमें हर तरह से मदद प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का हर क्षेत्र में समावेश किया जा रहा है, इसमें एचआरटीसी भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रदेश सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कैशलेस माध्यम से किराए के भुगतान के लिए बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई व एन.सी.एम.सी. कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। परिवहन क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यह सब निगम प्रबंधन और इसके कर्मठ कर्मचारियों के प्रयासों से ही संभव हो पाया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य को एचआरटीसी की स्वर्ण जयंती के मौके पर तैयार किया गया विशेष बैज भी लगाया गया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एचआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्वर्ण जयंती समारोह की बधाई देते हुए कहा कि एचआरटीसी की पहचान अपने कर्मचारियों की व्यवसायिकता और प्रतिबद्धता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आज एचआरटीसी बस में यात्रा करना आनंद और आकर्षण का पर्याय हैं। एचआरटीसी में प्रबंधन कौशल से ऑक्यूपेंसी में वृद्धि हुई है और लोगों में निगम के प्रति विश्वास बढ़ा है। एचआरटीसी एक जज्बा है, काम के प्रति समर्पण है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एचआरटीसी से भावनात्मक रिश्ता है। मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय रसील सिंह ठाकुर ने निगम की अनुकरणीय सेवा की है। एचआरटीसी रोजाना छह लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी को व्यावसायिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता यह घाटे के रूटों पर भी निरंतर सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्था लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। एक दिन में निगम द्वारा लगभग 50 लाख रुपये रियायती सफर की सेवा के लिए वहन किए जाते हैं।

प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम ने मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी 24 घंटे कार्य कर जनसेवा के प्रति समर्पित है।

प्रबंध निदेशक एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर ने 50 वर्षो के दौरान एचआरटीसी की स्वर्णिम यात्रा की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मान सिंह और महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर एचआरटीसी की 50 वर्षो की उपलब्धियों पर आधारित एक आकर्षक लघु नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वृत चित्र भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारी निदेशक डॉ. मुरारी लाल ने आभार प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

समारोह में विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, मेंबर बीओडी एचआरटीसी बलदेव ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, प्रबंध निदेशक एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप, निदेशक परिवहन डॉ. पंकज ललित, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी, वरिष्ठ अधिकारी, एचआरटीसी परिवार के सभी सदस्य, पेंशनर और गणमान्य उपस्थित थे।

एसजेवीएन लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से कर रही खिलवाड़

शिमला/शैल।. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सतलुज जल विद्युत परियोजना, एसजेवीएन पर आरोप लगाया है कि वह लुहरी जल

विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि हालांकि यह एक सरकारी उपक्रम है बाबजूद इसके इसकी कार्यप्रणाली बड़े धन्ना सेठों अम्बानी व अडानी की तरह है जहां लोगों की कोई भी आवाज नही सुनी जा रही है। एक पत्रकार वार्ता में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि गत दिन शिमला उपायुक्त की अध्यक्षता में एसजेवीएन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के समक्ष इस परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए इनके निराकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रदेश विधानसभा में भी उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एसजेवीएन ने सीएसआर का पैसा जो इस क्षेत्र के विकास में खर्च होना था,अन्यों जिलों में खर्च किया है। उन्होंने कहा कि यहां खनन से पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही इस परियोजना के पुन: सर्वे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से रामपुर व ठियोग विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। डंपिंग भी सही ढंग से नही हो रही है। यहां सेब व अन्य फसलें भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अभी तक भी कोई मुआवजा नही मिला है।

राठौर ने कहा कि एसजेवीएल अपने करार के अनुसार कार्य नही कर रहा है । उन्होंने कहा कि करार में स्पष्ट तौर पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी जो पूरी नही हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 400 से अधिक मजदूरों को परियोजना से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी से भी अन्याय सहन नही करेगी। उन्होंने एसजेवीएन से मांग की है कि उन्हें अपने करार को पूरा करते हुए प्रभावित परिवारों के हितों की पूरी रक्षा करनी होगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने धर्मगुरू श्रीश्री रविशंकर से भेंट की

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बंगलुरू के एनटीटीएफ के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा कर संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में युवाओं

को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए मार्केट की डिमांड के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

युवाओं को इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिसियल इंटेलिजंस और डाटा सांइस आधारित डिप्लोमा कोर्स करवाए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को स्वावलम्बी बनने का अवसर उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने एनटीटीएफ के प्रबन्ध निदेशक बी.वी. सुदर्शन से ऑटोमेशन, कनैक्शन, कलॉउड कम्पयूटिंग जैसे पाठयक्रमों के बारे में गहनता से विचार-विमर्श किया। इसके उपरांत उन्होंने कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के टेक्निकल एडवाइजर के.एल झाला के साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में फार्मा के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और उनके कौशल संवर्धन की दिशा में संयुक्त प्रयास करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का फार्मा हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और इससे फार्मेसी के बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बंगलूरू में धर्मगुरू श्री श्री रविशंकर से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने धर्मगुरू के साथ युवा शक्ति को नशे से बचाने की आवश्यकता के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को हिमाचल में युवाओं को नशे की दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह भी किया। उन्होंने धर्मगुरू को बताया कि हिमाचल में नशे के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति को अपनाया जा रहा है और नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित आईटीआई केंद्रों का भी दौरा किया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भाजपा की आक्रामकता के राजनीतिक मायने क्या है?

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डी. ए. जो जनवरी 2023 से देय था देने की घोषणा की है। इसी के साथ प्रदेश के सारे कर्मचारीयों को निगमों बोर्डो सहित वेतन की अदायगी भी इसी माह की 28 तारीख को करने की घोषणा करके इस आश्य के आदेश भी जारी कर दिये हैं। पैन्शनरों को भी यह अदायगी 28 तारीख को ही हो जायेगी। मुख्यमंत्री का यह फैसला प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति पर उठते सवालों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसी फैसले के साथ यह सवाल भी उठाना शुरू हो गया है कि क्या भविष्य में भी यह भुगतान इसी तरह सुनिश्चित हो पायेंगे। इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अन्य लोगों के भुगतान भी इसी तरह समय पर हो जायेंगे जो कर्मचारी नहीं हैं। क्योंकि काफी अरसे से ठेकेदार और दूसरे सप्लायर भी यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके भुगतान भी काफी अरसे से अटके पड़े हुये हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के तो संगठन है और वह अपनी आवाज इनके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्यो को फील्ड में अंजाम दिया जा रहा है यदि उनके भुगतान समय पर न हुये तो उससे विकास कार्यो पर ब्रेक लग जायेगी और वह सरकार के लिये और भी नुकसान देह स्थिति होगी। इसलिये वित्तीय स्थिति और उसके प्रबंधन का टेस्ट आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पैन्शनरों के यह भुगतान करने का ऐलान किया तो उस पर भी भाजपा ने तुरन्त यह कह दिया है कि यह सब कुछ केन्द्र द्वारा 1479 करोड़ की एडवांस अदायगी कर देने से संभव हुआ है। जबकि अब तक केन्द्र ने हिमाचल को उसके हिस्से से ज्यादा आदायगी नहीं की है। परन्तु भाजपा का सारा नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक यह सन्देश देने में लगा हुआ है कि प्रदेश सरकार केन्द्र के सहयोग के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। बल्कि जेपी नड्डा जब पिछले दिनों बिलासपुर आये थे तब जो ब्यान उनका आया वह विश्लेषकों की नजर में एक तरह का चुनावी भाषण ही था। भाजपा का हर नेता जिस तरह से सरकार के खिलाफ आक्रामक हो उठा है और आपदा राहत में घपला होने का आरोप लगा रहा है उससे यह कुछ अलग ही तरह का संकेत और संदेश जा रहा है। भाजपा नेता सुक्खू सरकार को एकदम असफल और भ्रष्टाचार में लिफ्त होने का तमगा देते जा रहे हैं। भाजपा के इन आरोपों का सरकार और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कारगर जवाब नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और सरकार कांग्रेस द्वारा ही विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सरकार के खिलाफ सौंपी अपनी ही चार्जशीट पर कोई कारवाई नहीं कर पा रही है। इससे सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वत: ही बल मिल जाता है। इस समय केन्द्र सरकार के सहयोग पर जहां मुख्यमंत्री फूटी कौड़ी भी न मिलने की बात कह रहे हैं वहीं पर उनके ही कुछ मंत्री इस सहयोग को रिकॉर्ड पर लाकर मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इस तरह सरकार में ही उठते इन अलग स्वरों का राजनीतिक अर्थ बदल जाता है। फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर धनबल के सहारे इस सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लग ही चुका है। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये एफ आई आर तक दर्ज है। एफ आई आर जांच में हरियाणा की पूर्व खट्टर सरकार के प्रचार सलाहकार पर भी आरोप आये हैं। अब हरियाणा में पुन: भाजपा की सरकार बन गयी है। हिमाचल में दल बदल का खेल नड्डा के अध्यक्ष काल में हुआ है। अब नड्डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो गये हैं लेकिन उस समय दल बदल से सुक्खू सरकार गिराई नहीं जा सकी। यह असफलता एक तरह से नड्डा के नाम पर भी है। लेकिन राज्यसभा चुनाव और उसके बाद के घटनाक्रम ने सुक्खू सरकार को अब तक चैन से बैठने नहीं दिया है। वेतन भत्ते निलंबित करने का रिकॉर्ड सदन के पटल पर आ गया है। इस समय सरकार के चार-पांच मंत्री किसी न किसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ तकरार में चल रहे हैं। कर्मचारी आन्दोलन की स्थिति पूरी तरह खत्म नही हुई है। मीडिया को पुलिस बल के माध्यम से डराने के प्रयास लगातार रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। जनता इस सरकार को ''टैक्स'' की सरकार का तमगा दे रही है। इस तरह मित्रों के अलावा हर वर्ग सरकार से पीड़ित है। भाजपा इस स्थिति पर बराबर नजर बनाये हुये है और यह सन्देश सफलतापूर्वक दे रही है कि केन्द्र के सहयोग के बिना सरकार एक दिन नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में जब कर्ज लेने की सीमा पार हो जायेगी तब प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन कैसे आगे बढ़ेगा उस पर सबकी निगाहें लगी हैं। माना जा रहा है कि सरकार अपने ही बोझ से दम तोड़ने के कगार पर पहुंच रही है। भाजपा इसी स्थिति की प्रतीक्षा में है और तब सरकार तोड़ने के प्रयास एक दम गति पकड़ लेंगे। उस समय तक यदि नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में कोई ठोस कदम न उठ सके तो सरकार और पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ जाएगी। भाजपा अपने ब्यानों से इसी संभावित बगावत को हवा दे रही है। माना जा रहा है कि भाजपा की आक्रामकता प्रदेश को चुनावों की ओर ले जाने का एक सुनियोजित प्रयास है।

आईजीएमसी के नॉन फंक्शनल ट्रामा सेंटर से ढाई करोड़ की चपत:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में एक और घोटाला सामने आया है। यह घोटाला ट्रामा सेंटर में मैन पॉवर उपलब्ध करवाने के नाम पर हुआ। डेढ़ साल से बंद पड़ा आईजीएमसी का नव निर्मित ट्रामा सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा था और वहां पर अलग-अलग समय में सपोर्टिव और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार के माध्यम से कर दी गई थी। अपने चहेतों को लाभ दिलवाने के लिए सभी कायदे कानून ताक पर रख दिये गये। एक बन्द पड़े ट्रामा सेंटर में सैकड़ों कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बिना एक भी मरीज का इलाज किये ट्रामा सेंटर के मैन पॉवर के नाम पर दो करोड़ तीस लाख का बिल सरकार पर लाद दिया गया। गौरतलब है कि मैन पॉवर के लिए आने वाले खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। यह केन्द्र द्वारा जनहित के लिए भेजे गये पैसों की खुलेआम लूट है। फाइनेंस प्रूडेंश और फाइनेंस डिसिप्लिन के नाम पर कर्मचारियों का वेतन और पेंशनधारकों की पेंशन रोकने वाले वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह से जनहित के काम में आने वाले पैसों को अपने चहेतों में बांटा जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हर दिन सुक्खू सरकार के कारनामें बाहर आ रहे हैं। नया मामला लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भेजे गये पैसे की बंदरबांट का है। केंद्र सरकार के सहयोग से बने आईजीएमसी के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने फीता काटने और पटिका लगवाने के शौक में मुख्यमंत्री ने पिछले साल 09 मार्च को कर दिया और उसी के साथ ही मैन पॉवर की भर्ती के लिये अपने चहेते ठेकेदारों को ऑर्डर भी दे दिया। अपेक्षित मैनपॉवर को ठेकेदारों ने ट्रामा सेंटर में नियुक्ति भी दे दी लेकिन सरकार ट्रामा सेंटर को फंक्शनल करना भूल गई। बिना इलाज किये हर महीनें ठेकेदार का बिल बनता रहा। धीरे-धीरे बढ़कर यह राशि 2 करोड़ 30 लाख हो गई। जिससे भुगतान के लिए अब ठेकेदारों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों ट्रामा सेंटर को फंक्शनल करने आये मुख्यमंत्री से भी ट्रामा सेंटर में तैनात कर्मचारियों ने मुलाकात की और वेतन न मिलने की शिकायत की। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न समय पर ट्रामा सेंटर के लिए अलग-अलग पदों पर जिसमें सपोर्टिव स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है के लिए भर्तियां निकाली और आउट सोर्स के माध्यम से उन्हें भरा गया। सूचना के अधिकार के तहत हासिल किये गये डॉक्यूमेंट के आधार पर पता चलता है कि रेडियो ग्राफर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय ट्रॉली मैन सफाई कर्मचारी के कुल 126 पदों पर अलग-अलग समय में नियुक्तियां हुई। हैरानी की बात है कि जो ट्रॉमा सेंटर अब फंक्शनल हुआ है उसके लिए कई महीनों या साल भर पहले से ही कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है।

इसके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल करने में 19 महीने का वक्त क्यों लगाया? क्या बने बनाये प्रोजेक्ट का बार-बार फीता काटना ही व्यवस्था परिवर्तन है। जहां केन्द्र सरकार के कामों का फीता काटा जाये और केंद्र सरकार को कोसा जाये। क्योंकि जो पैसा घोटाले के माध्यम से उड़ाया जा रहा है वह भी केंद्र सरकार से आया है और जिस पैसे से ट्रामा सेंटर और कैंसर टर्शरी सेंटर बन रहा है वह भी केंद्र सरकार का है। सरकार बस फीता कटर बनकर फीता काटे जा रही है।